interest in the land development banks. This Committee has just started its work.

राज्यों में मात्स्यकी के विकास के लिये 13.48 करोड़ रुपये की परियोजना

3000. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सहायता लेने हेतु राज्य में मात्स्यकी के समग्र विकास के लिये 13.48 करोड़ रुपये की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी राज्यों में मुख्य रूप से मछलियों के विकास के लिये विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय स्तर पर एक परियोजना तैयार की जा रही है ;

(ग) क्या जून, 1976 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया था कि राज्य के बड़े जलाशयों में मात्स्यकी के विकास के लिये मात्स्यकी विकास निगम की स्थापना की जाये और वर्ष 1978–79 के बजट में इस प्रयोजनार्थ 20 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस निगम की स्थापना के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । राज्य में मात्स्यकी के समग्र विकास के लिए 13.48 करोड़ रुपए की कुल लागत से अन्तर्देशीय मात्स्यकी के विकास से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना विश्व बैंक के दल को, जिस ने भारत का दौरा किया था, प्रस्तुत की गई थी ।

(ख) जनवरी, 1978 में ऐसी उपर्युक्त अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजनाओं का पता लगाने के लिए, जो कि विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए आर्थिक दृष्टि से संभाव्य हों, एक विश्व बैंक अभिज्ञान मिशन ने भारत का दौरा किया । प्रारम्भिक संकेतों से पता चलता है कि देश में डिमपोना के उत्पादन के लिए विश्व बैंक बहुराज्यीय परियोजना की बात सोच सकता है । अभिज्ञान मिशन की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने 1978–79 के दौरान राज्य मात्स्यकी विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है और राज्य के वर्ष 1978–79 के बजट में मात्स्यकी विकास निगम की स्थापना के लिए, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन है, 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(घ) राज्य मात्स्यकी निगम की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया करने का कोई प्रावधान नहीं है । ऐसी गतिविधियों के लिए राज्य योजना में निधि की व्यवस्था की जाती है ।

राष्ट्रपति भवन, राज भवनों और मन्त्रियों के आवासों आदि पर व्यय

3001. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जून, 1977 को प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार राष्ट्रपति भवन, राज भवनों और मंत्रियों के निवास-स्थानों आदि पर होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो 7 जून, 1977 से 7 जून, 1978 की अवधि के दौरान इस व्यय में कितनी कमी की गई ?